International Journal of Applied Research 2017; 3(8): 951-956

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(8): 951-956
www.allresearchjournal.com
Received: 13-06-2017
Accepted: 18-07-2017

डॉ. कविता भटनागर
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग, जी डी एच जी कालेज, मुरादाबाद] उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. कविता भटनागर
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग, जी डी एच जी कालेज, मुरादाबाद] उत्तर प्रदेश, भारत

भारत में मुद्रास्फीति - कारण और प्रभाव

डॉ. कविता भटनागर

सारांश
मुद्रा और अर्थव्यवस्था का आपसी सम्बंध बहुत नजदीकी है। मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पडता है । भारत में आजादी के बाद से योजना बद्ध विकास को अपनाया गया था । हमारे देश में कभी बहुत तेज और कभी न्यून मुद्रास्फीति की दर बनी रही है जिससे हमारी विकास दर प्रभावित होती रही है। विकास के लिए हमनें घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई और कीमतों में लगातार इजाफा होता रहा है । रिजर्व बैंक और सरकार ने मौदिक और राजकोषीय उपाए अपनाए है जिससे कुछ हद तक हम मुद्रास्फीति पर काबू पाने मे सक्षम हुए है। भारत में नीतिनिर्माताओं ने 3% से 6% की मुद्रास्फीति की दर रखने के प्रयत्न किए है जो आशिंक सफल हो रहे है।

कूटशब्द: द्रास्फीति, अर्थव्यवस्था, मुद्रा संकुचन

प्रस्तावना
मुद्रा एवं अर्थव्यवस्था का जल और जीवन के समान परस्पर घनिष्ठ सम्बंध है । जिस प्रकार जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना करना असम्भव है । किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्तर स्थिर नही रह सकता है, यह परिवर्तनशील होता है और इसका कीमत के स्तर से विपरीत सम्बंध होता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति की संकेतक होती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी मुद्रा संकुचन की । हरेक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन की स्थिति आती रहती है । विकासशील देश के लिए सीमित मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति आवश्यक मानी जाती है लेकिन नियंत्रण के अभाव में यह मुद्रास्फीति सारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की क्षमता रखती है ।

स्वतंत्रता के उपरांत विकास की दर को गति देने के लिए भारत ने योजना बद्ध विकास का मार्ग अपनाया । विशेष बात यह है की आयोजना काल के पहले दशक में 1950- 51 से 1960-61 तक भारत में मुद्रास्फीति की दर बहुत संतोषजनक रही । वस्तुतः पहले योजना काल में कीमतो का स्तर कम हुआ था । थोक मूल्यों पर आधारित सूचकांक (आधार वर्ष 60-61=100) जो 1950-51 में 89 था वह घटकर

योजना काल के अंतिम वर्ष में(1955-56) में मात्र 74 रह गया । इसका श्रेय 1952-53 में बंपर खाद्यान्न उत्पादन को दिया गया था जिसका मूल कारण उन वर्षों में अच्छे मानसून को दिया जा सकता है । मुद्रा की पूर्ति में उत्पादन की मात्रा, खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले बहुत कम वृद्धि हुई, इसलिए कीमतों का दबाव कम रहा।

1960-61से 1970-71 का दशक सामान्य मुद्रास्फीति का काल था। इस पूरे दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर 6.4 रही थी । 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण स्फीतिक कारकों में वृद्धि नजर आई । फिर इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध।(1965) और अकाल की स्थिति में खाद्यान्नों और जरूरी सामान की कीमतों में तेज वृद्धि हुई । 1966-67 मैं मुद्रास्फीति की दर 13.9% रही जो पूर्ति के मुकाबले मांग की अधिकता के कारण थी ।1968-69 में फिर एक बार बंपर खाद्यान्नों के उत्पादन और निर्यात से मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक (-1.1) हो गई थी ।

सत्तर के दशक और अगले 20 वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि देखी गई थी। इस अवधि में लगातार अनेक वर्षों तक दौड़ती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति भी बनी रही थी। 1972-73 खरीफ की फसल का उत्पादन प्राकृतिक कारणों से बहुत कम हुआ , तेल उत्पादक देशों ने चार बार तेल की कीमतों में वृद्धि की और पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध(1971) लड़ना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप 1972-73 में 12.3%, 1973-74 में 20.2% और1974- 75 में 23.98% की दर से कीमतें बढी । सरकार को इस समय आम जनता का बढ़ता हुआ असंतोष सहन करना पड़ा, जिसके कारण अगले ही वर्ष सरकार ने अनेक सख्त मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किए । इन मौद्रिक और राजकोषीय उपायों और जमाखोरों पर नियंत्रण के कारण अगले ही वर्ष मुद्रास्फीति की दर पर अंकुश लगा और इस बार फिर ऋणत्मक वृद्धि दर(-1.1) देखी गई। इन उपायों का प्रभाव सिर्फ अगले 3 वर्षों तक ही रहा, जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर सामान्य स्तर पर बनी रही, लेकिन दशक के अंतिम वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मुद्रास्फीति की दर एक बार फिर 10% के ऊपर हो गई थी ।

1980-81 से 1990 -91 के काल में मुद्रास्फीति की दर में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। सामान्य जनता को बढ़ती हुई कीमतों से कोई राहत नहीं मिली। इस काल में अधिकतम मुद्रास्फीति की दर 18.2% (1980-81) और न्यूनतम 4 .4% (1985-86) रही ।

1990-91 में आर्थिक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रिय दवाव के कारण देश में उदारीकरण के सुधारों को अपनाया गया था । इसके बाद ही आशा की जा रही थी की मुद्रा की पूर्ति और मांग में बेहतर सामंजस्य के कारण मुद्रास्फीति की दर कम होगी लेकिन1990-91 से 1997- 98 के दौरान 7 वर्षों मे से 4 वर्षों में मुद्रास्फीति 10% से ऊपर के स्तर पर ही बनी रही। 1991 में खड़ी संकट, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्यान्नों विशेष रूप से अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि से सिर्फ 1993- 94 को छोड़कर लगभग सभी वर्षों में मुद्रास्फीति की दर दो अंको को छूती रही थी । 1998- 99 कृषि उत्पादन में मात्र 1% की वृद्धि दर्ज की गई लेकिन पूरे साल के आधार पर मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर 5.50% पर बनी रही जो 1997- 98 के 4.8% के स्तर से थोड़ा सा ही ज्यादा थी। जनवरी 2000 तक मुद्रास्फीति की दर 2.9% के निम्नतम बिंदु तक जा पहुंची। 2001-02 में मुद्रास्फीति सामान्य स्तर पर रही लेकिन 2002-03 से इसमें खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण फिर वृद्धि देखी गई। 2007-08 तक मुद्रास्फीति की यही स्थिति रह जिसमें औसतन 5.6% की वृद्धि देखी गई। 2008 की विश्वव्यापी मंदी के काल में स्फीतिक दबाव फिर बढ़ने लगे और अगस्त-सितंबर 2008 तक फिर से यह दहाई के अंक के ऊपर पहुंच गई । केंद्रीय बैंक ने सख्त मौद्रिक नीति की घोषणा की जिससे एक बार फिर मुद्रास्फीति की दर 2009 में शून्य के स्तर पर पहुंच गई। 2009 से 2012 तक मुद्रास्फीति 4% से 10% के मध्य बनी रही जो कुछ हद तक सहनयोग्य

थी । 2013-14 में भी इसमें व्यापक उतार-चढ़ाव होते रहे थे ।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने 2015- 16 से थोक मूल्य सूचकांक के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी मुद्रास्फीति की दर मापने के लिए प्रस्तुत किया और इस आधार पर मुद्रास्फीति की दर शुरूआती वर्षो में 6% से कम रखने और बाद के वर्षों के लिए 4%(+/- 02) तक करने पर जोर दिया । यह भी निश्चित किया गया है कि 3 तिमाही तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहने पर जवाबदेही निश्चित की जाएगी और इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सार्वजनिक वक्तव्य देना होगा । मुद्रास्फीति पर उर्जित पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुद्रास्फीति की लक्षित दर को प्रतिशत 4% निश्चित करने की सिफारिश की थी । कमेटी ने उच्च मुद्रास्फीति की दर के दुष्प्रभावों को लक्षित करते हुए कहा था कि यह बचत और निवेश पर प्रतिकूल असर डालती है और आर्थिक समृद्धि में रुकावट पैदा करती है ।

मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित स्तर तक रखने के लिए 205-6 में भारतीर रिजर्व बैंक अपनी प्राथमिकता भी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4% तक लाने की कवायद शुरू की है । इसके लिए केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2016 तक 6% और मार्च 2017 तक 5% तक लाने का लक्ष्य रखा है । 2016 की पहली और दूसरी तिमाही तक दालों और सब्जियों की कीमतों मे बढोतरी के कारण महगाँई का बढना बना रहा है , लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति की दर 6% के नीचे बनी रही है । यद्यपि खाद्य पदार्थों के दामों से महगाँई उच्च स्तर की ओर अग्रसर है, लेकिन राजकोषीय घाटे के 3.9% के स्तर पर रहने के कारण मुद्रा की अनियमित पूर्ति पर रोक लग रही है और मुद्रास्फीति को कम रखने में मददगार हो रही है । यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2017 मे मध्य तक वस्तु एवम सेवा कर अधिनियम लागू होने पर स्फीति कारक प्रभावों में कमी आयेगी । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) के आधार पर मापी जाने वाली मुद्रास्फीति जुलाई माह में वर्ष मे 3.7% के न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है, लेकिन मानसून के विलम्ब हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों की बढत का इस पर प्रभाव पडना अवश्यम्भावी है । इस वर्ष कच्चे तेल की कीमतों ने भी मुद्रास्फीति को सहारा प्रदान किया है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कच्चे तेल की कीमत जनवरी 2016 तक 28 अमेरीकी डालर प्रति बैरल तक नीचे आ चुकी है ।

तालिका संख्या 1: विभिन्न कीमत सूचकांक पर आधारित सामान्य मुद्रा स्फीति

	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
थोक मूल्य सूचकांक	6.9	5.2	1.2	-3.7
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	10.2	9.5	5.9	4.9

स्रोत – आर्थिक सर्वेक्षण – 2015-16

यदि हम पिछले चार दशकों (1977-2016) का अध्ययन करें तो पायेंगे कि इस काल मे मुद्रा स्फीति के चार दौर रहे है – 1977 से 1999 तक के 23 वर्षो में औसतन 9% की उच्च मुद्रास्फीति , 2000 से 2005 तक के पाँच वर्षों में औसतन 4% तक की निम्न मुद्रास्फीति, 2006-2014 के आठ वर्षों फिर औसतन 9% की तीव्र मुद्रा स्फीति और 2014 के बाद फिर से निम्न मुद्रास्फीति का दौर चालू हुआ है । अगले कुछ वर्षों तक इस निम्न मुद्रा स्फीति के बने रहने की सम्भावनाएं है ।

मुद्रा स्फीति मुद्रा की पूर्ति और माँग के बीच असंतुलन की स्थिति है । क्राउथर व अन्य मुद्रावादी अर्थशास्तियों के अनुसार मुद्रा स्फीति मुद्रा की मात्रा मे अत्याधिक प्रसार के कारण उत्पन्न होती है जबकि फिस्कलवादी अर्थशास्त्री मुद्रा स्फीती के लिए अमौद्रिक कारण वस्तुओं की माँग का उपलब्ध पूर्ति से

अधिक हो जाना मानते है । कीन्स नें मुद्रा स्फीति को पूर्ण रोजगार से सम्बंध किया है । उनके अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के बाद मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर माँग तो बढ़ जाती है परंतु उत्पादन मे वृद्धि सम्भव नही हो पाती है । फलत: माँग आधिक्य से कीमतें बढ़ जाती है , यही असल मुद्रा स्फीति की स्थिति है । अर्थशास्त्रियों के अनुसार रेंगती हुई मुदास्फीति जिसमें मूल्यों में वृद्धि की दर काफी कम होती है तो यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होती है और यह विकास को बल प्रदान करती है । इसके विपरीत यदि मूल्यों मे वृद्धि अधिक होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है और बहुत अधिक होने पर पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देती है ।

मुद्रा स्फीति को उत्पन्न करने में दो प्रकार के कारण जिम्मेदार होते है – 1) मौद्रिक आय या माँग को प्रभावित करने वाले कारक, और 2) उत्पादन या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक । मौद्रिक आय या माँग को प्रभावित करने वाले कारको मे मुद्रा की पूर्ति, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि , घाटे की अर्थव्यवस्था , अनुत्पादक व्यय मे वृद्धि, निजी क्षेत्र का विस्तार , काला धन और ऋणों का भुगतान आदि कारक है जबकि उत्पादन या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में साधनों में कमी, प्राकृतिक आपदाये, आधुनिक उत्पादन तकनीकों का अभाव. सरकार की प्रतिकूल कर तथा व्यापार नीति विलासिता की वस्तुओं का अति उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का दवाब आदि कारक है ।

मुद्रा की माँग और पूर्ति का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव पडता है । मुद्रा की माँग पर आय के स्तर और मुद्रा धारित करने की अवसर लागत का प्रभाव रहता है । यह अनेक व्यवहारगत और संस्थागत कारको से भी संचालित होती है । इन कारको मे बैंकिग आदतें , परिष्कृत भुगतान और निपटान प्रणाली और वित्तीय क्षेत्र के विकास शामिल है । भारतीय रिजर्व बैक की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा की माँग को अनेक प्रतिरोधात्मक कारक भी प्रभावित करते है , जैसे पर्व, महोत्सव , चुनाव और हडताल आदि । 2015-16 मे मुद्रा की माँग में तेज बढोतरी कई राज्यो मे हुए चुनाव जैसे प्रतिरोधात्मक कारको के कारण हुई थी जबकि सामान्य आय और व्याज दरें कमोबेश स्थिर बनी हुई थी । मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारको मे से आरक्षित मुद्रा के वर्ष 2015-16 में असामान्य विस्तार के कारण मुद्रा की माँग में पिछ्ले कई वर्षो से अधिक बढोतरी हुई है जबकि पहली बार मुद्रा-जमा अनुपात (सी /डी) मे बढत ने मुद्रा गुणक को मंद किया है ।

भारत एक विकाससील देश है और उस पर मुद्रा स्फीति को प्रभावित करने वाले दोनो कारकों का समान प्रभाव पडता है । भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास के उद्देश्य से निवेश के आकार में वृद्धि की जाती है । निवेश बढाने पर लोगों की मौद्रिक आय बढ जाती है और सामान्य जीवन स्तर नीचा होने के कारण लोग अपनी आय में हुई वृद्धि का उपयोग उपभोग स्तर बढाने के लिए करना चाहते है । उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का अभाव होता है और माँग बढने से उपभोग की वस्तुओं में तत्काल वृद्धि करना सम्भव नही हो पाता है । माँग और पूर्ति का यह असंतुलन उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बढा देता है । सेवाओं की माँग भी बढने लगती है । जिससे लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के देशों मे मुद्रास्फीति सरंचनात्मक असंतुलन का परिमाण है । भारत में मुद्रास्फीति के लिए निम्न संरचनात्मक कारक है -

घाटे की अर्थव्यवस्था: योजना काल के आरंभ से ही भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाना आरंभ कर दिया था। इसका मूल कारण था पर्याप्त मात्रा में राजस्व की प्राप्ति ना हो पाना और विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होना। प्रत्येक विकासशील देश के लिए यह आवश्यक है की विकास की गति को तीव्र करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश और पूंजी हो। विकास के आरंभिक काल में उसे विदेशी ऋण भी आसान किस्तों पर नहीं मिल पाते हैं और

जनता से भी बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्र करना असंभव होता है क्योंकि जनता तो स्वयं गरीबी की मार झेल रही होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार की कमियां थी। हम यह नहीं कह सकते की सरकार का वित्त प्रबंधन ठीक नहीं था क्योंकि बिना घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाएं देश में विकास कार्य पूरे नहीं हो सकते थे। लेकिन यदि घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाकर तीव्र आर्थिक समृद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तो मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में लगभग 954 करोड़ और 1135 करोड़ रुपए घाटे का वित्त प्रबंधन किया गया था। इसके बाद भी जब जब सरकार को अर्थव्यवस्था में तरलता की समस्या आती थी, सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेती रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में 850 करोड़ रुपए के घाटे का और 5.6% विकास की दर का अनुमान लगाया गया था, जबकि योजना के पूरे कार्यकाल में घाटा दो हजार करोड़ से ज्यादा और विकास की दर मात्र 3.3% रही। इस काल में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति लगभग 20% के आसपास रही । 1970 का दशक भारत में मुद्रास्फीति के लिए सर्वाधिक रोमांचकारी दशक रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था को नियमित कर दिया गया हो क्योंकि सातवीं योजना (1985-90) में 14000 करोड रुपए के घाटे के वित्त प्रबंधन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन योजना काल के अंत में वास्तविक घाटा 34000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर रहा। इस योजना काल हमें अकाल की समस्या का सामना भी करना पड़ा लेकिन विकास दर 6% केआसपास रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में बहुत अधिक घाटे का वित्त प्रबंधन था जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित कर पाना असंभव ही रहा था ।

जनसंख्या में लगातार वृद्धि: पिछले 5 दशकों से भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 2.2 प्रतिशत रही है। शहरी जनसंख्या का अनुपात 1951 में 18% से बढ़कर 2006 में 29.8% हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं, शिक्षा, परिवहन, आवास, जल, विद्युत और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। सीमित संसाधनों के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार जो व्यय करती है, वे सभी कारक मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

काले धन का प्रभाव: काला धन है वह धन है जिस पर कर देय है पर कर अदा नहीं किया जाता है और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। टैक्स की चोरी करने वालों, सटोरियों और जमाखोरों के पास यह धन प्रचुर मात्रा में जमा होता है। इस धन का कोई भी उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है बल्कि यह धन विलासिता की वस्तुओं और स्वर्ण आभूषणों पर खर्च होता है। इस धन के उपयोग से कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा का प्रसार होता है। प्राकृतिक कारणों से फसल खराब हो जाने की स्थिति में बडे किसानो और थोक बाजारियों ने हमेशा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की है और सरकार उन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने मे असफल रही है।

ऋणों का भुगतान: जब कभी सरकार लिए गये सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करती है तो जनता के पास क्रय शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है जिससे बढी हुई क्रय शक्ति का उपयोग वस्तुओं की मांग के लिए किया जाता है। उत्पादन इस अनुपात में बढ नही पाता है और वस्तुओं की कीमत में इजाफा हो जाता है। कीमतों की यह वृद्धि मुद्रास्फीती के रूप मे जाहिर होती है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय दोनो उपाय अपनाए है –

1. सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई है।
2. बैंको की साख पर बैंकों की दर के द्वारा नियंत्रण लगाए गये है।

3. ख़ाद्यान्नों जैसे गेहूँ , चावल, चीनी आदि पर राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गयी है।
4. अनेक बचत योजनायें जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र व सुरक्षा बचत पत्र पर व्याज की दर बढाई गयी है जिससे लोग इन योजनाओं की तरफ आकृषित हो। भारत में मुद्रास्फीति की समस्या बहुत चुनौती पूर्ण है ।

आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को हम अलग-अलग करके नही देख सकते है । आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुद्रा का विस्तार किया जाना आवश्यक है वहीं घाटे की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति छिपी रहती है । मुद्रा के अनियंत्रित प्रसार को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि किया जाना आवश्यक है, मात्र मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रख कर कीमतों मे वृद्धि को रोक पाना असम्भव है । घाटे की अर्थव्यवस्था का उपयोग आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से उत्पादन की महत्वपूर्ण मदों मे किया जाना चाहिए ।

संदर्भ

1. आर चक्रवर्ती-(1989) द बिहेवियर आफ इंडस्ट्रियल पालिसी इन इंडिया
2. इकोनोमिक सर्वे (2015-166)- भारत सरकार
3. योजना पत्रिकाएं- 2015,2016
4. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन- 2015-16